भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4961
(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन

4961. श्री कनकमल कटाराः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन-दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है और इसका क्या परिणाम हु है; और
(ग) देश में सर्वाधिक ग्रामीण-पलायन दर वाले राज्यों के नाम क्या है और इनके बीच पलायन की तुलनात्मक दर कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): 'भारत में पलायन 2007-2008' विषय पर नवीनतम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जुलाई, 2007 से जून, 2008 के दौरान कराया गया था (64वां दौर)। एनएसएस के 64वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण पलायन का राज्य-वार अनुपात **अनुबंध** में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय रोजगार के अवसरों के सृजन, धारभूत वश्यकताओं की पूर्ति तथा ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं चला रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी ऐसे ग्रामीण परिवारों को दी जाती है, जिसके व्यस्क सदस्य श्रम कार्य करने को इच्छुक हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों पर देश के अधिसूचित सूखा प्रभावित या प्राकृतिक पदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा 50 अतिरिक्त दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण गरीब परिवारों के सदस्यों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय

ग्रामीण जीविका मिशन (डीएवाई-एन रएलएम) चलाया जा रहा है। यह विभाग श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएम रएम) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'रुर्बन क्लस्टर' नामक ऐसे 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का विकास करना है, जिनमें विकास की अंतर्निहित संभावना हो। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच मौजूद अंतर को कम करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन में कमी लाना और अंततोगत्वा शहर जा चुके लोगों को भी वापस ग्रामीण क्षेत्रों में लाना है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी लाने के लिए ग्रामीण जनसमुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से धारभूत वश्यकताओं की पूर्ति करने और ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने के लिए प्रधान मंत्री वास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भी चलाई जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वतंत्र अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चलता है कि गांवों से शहरों की ओर पलायन में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के कारण कमी ई है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.7.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 4961 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पलायनकर्ताओं का अनुपात (प्रति 1000)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पलायनकर्ताओं का अनुपात (प्रति 1000)
1	□ ंध्र प्रदेश	282
2	अरुणाचल प्रदेश	8
3	असम	120
4	बिहार	189
5	छत्तीसगढ़	295
6	दिल्ली	339
7	गोवा	212
8	गुजरात	299
9	हरियाणा	298
10	हिमाचल प्रदेश	378
11	जम्मू और कश्मीर	174
12	झारखंड	156
13	कर्नाटक	273
14	केरल	333
15	मध्य प्रदेश	268
16	महाराष्ट्र	329
17	मणिपुर	6
18	मेघालय	33
19	मिजोरम	110
20	नागालैंड	76
21	ओडिशा	280
22	पंजाब	312
23	राजस्थान	288
24	सिक्किम	300
25	तमिलनाडु	220
26	त्रिपुरा	110
27	उत्तर प्रदेश	256
28	उत्तराखंड	344
29	पश्चिम बंगाल	272
30	अडमान और निकोबार द्वीप समूह	533
31	चंडीगढ़	672
32	दादर और नगर हवेली	372
33	दमन और दीव	503
34	लक्षद्वीप	281
35	पुदुचेरी	242
	अखिल भारत	**261**